



1. राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है— राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी।
2. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों से अपने कर्तव्यों और मताधिकार का पालन करने का आह्वान किया।
3. टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में आज "विशेष गहन पुनरीक्षण पर जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया।
4. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय केन्द्र की ओर से कल से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि संविधान राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला है और यह राष्ट्र को आगे बढ़ाने, औपनिवेशिक मानसिकता के स्थान पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण स्थापित करने का मार्गदर्शक ढाँचा है। उन्होंने कहा कि संविधान लोगों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने के लिए एक अत्यंत प्रभावी ढाँचा प्रदान करता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि भारतीय संसद विश्व के कई देशों के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने उल्लेख किया कि संविधान निर्माता यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि संविधान के माध्यम से लोगों की सामूहिक और व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा हो।

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि संविधान, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लाखों देशवासियों के सामूहिक ज्ञान, बलिदान और सपनों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महान विद्वानों, प्रारूप समिति और संविधान सभा के सदस्यों ने करोड़ों भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गहन विचार प्रस्तुत किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संविधान के मार्गदर्शन में देश सुशासन और सामाजिक-आर्थिक विकास की परिवर्तनकारी यात्रा पर अग्रसर है। लोकसभा अध्यक्ष ने संविधान सभा के सभी सदस्यों के साथ, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद और संविधान निर्माता के रूप में डॉ. भीमराव अंबेडकर को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि यदि संविधान का अक्षरशः पालन किया जाए, तो भारत दो हजार सैंतालीस तक एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने नौ भाषाओं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया। द्वीपसमूह में भी संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर देश के नाम पत्र लिखकर उन्नीस सौ उनचास में संविधान को ऐतिहासिक रूप से अंगीकार किए जाने का स्मरण किया है। राष्ट्र की प्रगति में संविधान की स्थायी भूमिका का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि दो हजार पन्द्रह में सरकार ने इस पवित्र दस्तावेज़ के सम्मान में छब्बीस नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखने और अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मज़बूत करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा भारत एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है।



राष्ट्रीय कानून दिवस के अवसर पर आज अंडमान विधि कॉलेज ने राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सहयोग से एक रैली का आयोजन किया। इस रैली में विधि कॉलेज के प्रवक्ता, कर्मियों और विद्यार्थियों के साथ प्राधिकरण कर्मियों और अधिकारियों ने भाग लिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय, सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर के रजिस्ट्रार राशिद आलम ने कॉलेज के प्राचार्य डॉ. पी.वी.एन. सरमा की उपस्थिति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने 'मेरा संविधान, मेरा स्वाभिमान' के नारे लगाए। कॉलेज परिसर में, छात्रों ने सामूहिक रूप से प्रस्तावना पढ़ी। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन किए गए।



टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के चुनावी साक्षरता क्लब की ओर से आज "विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर पर कॉलेज के प्रशिक्षुओं के लिए जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-शिक्षकों के बीच चुनावी प्रक्रिया के महत्व और भारत के चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण गतिविधियों के बारे में जानकारी देना था। सत्र के दौरान स्वीप के नोडल अधिकारी डॉ. एन. बालाकृष्णन ने वोट के अधिकार और एसआईआर के महत्व के बारे में जानकारी दी। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स सेंथिल ने उम्मीदवारों को मतदाताओं के लिए पात्रता मापदंड, एन्यूमरेशन प्रोसेस और एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में बताया। इस सत्र में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी, वोट देने के अधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में नागरिकों की जिम्मेदारी के महत्व पर बल दिया गया।



भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय केन्द्र और **EIACP** केन्द्र की ओर से वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के तहत द्वीप पारिस्थितिकीय तंत्र के तटीय और समुद्री जैव-विविधता पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कल से उनतीस नवम्बर तक चलने वाले इस कार्यशाला में भारतीय तटरक्षक बल, आई एन एस जरावा, भारतीय सेना, पुलिस, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, पशुपालन पालन और पशु चिकित्सा विभाग, शिक्षा और अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य के प्रतिभागी भाग लेंगे। यह कार्यक्रम भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से आयोजित की जा रही है।



रक्षा मंत्रालय ने अगले वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह से पहले **MyGov** के सहयोग से प्रत्येक नागरिक विशेषकर छात्रों और युवा कलाकारों के लिए देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु तीन प्रतियोगिताएँ शुरू की हैं। इन प्रतियोगिताओं में चित्रकला, निबंध, गायन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शामिल हैं। मंत्रालय ने कलाकारों को आत्मनिर्भरता, नवाचार और सतत विकास की ओर देश की यात्रा को दर्शाने वाली उत्कृष्ट कृतियाँ बनाने के लिए आमंत्रित किया है। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को एक विशेष प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा।



शिक्षा निदेशालय की ओर से उनतीस नवंबर को राज्य पुस्तकालय के सम्मेलन कक्ष में यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए एक मार्गदर्शी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह नौ बजे आरंभ होगा। विभाग ने कहा है कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे इच्छुक उम्मीदवार इसमें भाग ले सकते हैं। सत्र के दौरान, **UPSC** मेंटर्स और प्रशासनिक अधिकारी उम्मीदवारों को जानकारी प्रदान करेंगे।



अंडमान निकोबार राज्य खेल परिषद, कोच और इंस्ट्रक्टर के विभिन्न बीस पदों पर अनुबंध के आधार पर एक साल के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने वाले पुरुष उम्मीदवार की आयु अट्ठारह से पैंतालीस वर्ष और महिलाओं के लिए अट्ठारह से पचास वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन खेल परिषद के महासचिव के पास सत्रह दिसंबर शाम चार बजे तक जमा कर सकते हैं।

